संविधान के नीति निर्देशक तत्त्व भारतीय राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का निर्देश देते हैं जिसमें :

1. सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे [अनुच्छेद 38(1)];
2. सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो [अनुच्छेद 39(क)];
3. राज्य आय की असमानताएं कम करने और धन का संकेंद्रण न होने देने का प्रयास करेगा [अनुच्छेद 38(2),39(ग)];
4. राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने व शिक्षा पाने को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा [अनुच्छेद 41 व 47]

दुर्भाग्यवश, भारतीय संसद पर प्रभुत्व रखने वाले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने भारतीय संविधान के निर्माताओं की इन संकल्पनाओं को तिलांजलि देने का निर्णय ले लिया है और देश के लोगों के हितों से संबंधविच्छेद कर लिया है। 1991 में देश की अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करने का निर्णय लेने के बाद, वे देश को सिर्फ और सिर्फ विदेशी और देशी भीमकाय निगमों की नग्न नफाखोरी के लिये चला रहे हैं।

- विशालकाय कॉरपोरेट घराने गरीबों पर निर्मम हमला बोल रहे हैं। लाखों लोगों को उनकी जमीन-जंगल-पानी-संसाधनों से बेदखल किया जा रहा है — विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्प, विशाल आधारभूत प्रकल्प, गोल्फ मैदान, विलासी गृह प्रकल्प इत्यादि बनाने के लिये।
- भारतीय कृषि को जानबूझकर उद्ध्वस्त किया जा रहा है — ताकि उसपर महाकाय विदेशी कृषि-व्यावसायिक निगमें अपना कब्ज़ा जमा सकें। परिणामस्वरूप, पिछले डेढ़ दशकों में लगभग ढाई लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं।
- लाखों की तादाद में लघु उद्योग बंद पड़ रहे हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, यहां तक कि सरकारी बीमा कंपनियों व बैंकों को भी, कौड़ियों के मोल इन डाकुओं के हवाले किया जा रहा है।
- अत्यावश्यक सेवाओं का निजिकरण किया जा रहा है, ताकि निगमें इनपर नियंत्रण स्थापित कर उनको नफा कमाने का साधन बना सकें।
    - सरकारी स्कूलों व अस्पतालों को बंद या फिर उनका निजिकरण किया जा रहा है; दवाओं की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं; स्कूल-कालेजों की फीस आसमान छूने लगी हैं; बिजली मंहगी हो गयी है; बसों के किराये बढ़ गए हैं; राशन व्यवस्था समाप्त की जा रही है।
- आज नौजवानो के लिये ढंग कि नौकरियां ही नहीं हैं, शायद लगभग आधी आबादी बेरोजगार या अर्ध-बेरोजगार है।
- देश एक भयंकर पर्यावरणीय विध्वंस की तरफ बढ़ रहा है। निगमों को बेरोकटोक जंगल काटने, सागरीय कृषि के नाम पर समुद्रतटीय क्षेत्रों को नष्ट करने, भूजल का अति दोहन करने, हमारी नदियों-मिट्टी-भूजल-हवा को प्रदूषित करने की खुली छूट दी जा रही है।

परिणाम:

- एक तरफ, अमीर और अधिक अमीर हो रहे हैं: देश के 56 अरबपतियों की संपत्ति देश के GDP का 10% के बराबर है, और भारत के 7800 अति धनाढ्यों की संपत्ति GDP का 50% के बराबर है!
- तो दूसरी तरफ, गरीब और गरीब हो रहे हैं:
    - 75% आबादी को दो वक्त का भरपेट भोजन नही मिलता है।
    - 50% बच्चे (5 वर्ष से कम आयु) कुपोषित हैं।
    - 42% बच्चे आठवीं कक्षा के पहले स्कूल छोड़ देते है।
    - हर साल लाखों बच्चे निवारणीय रोगों से मरते हैं।

जैसे-जैसे आर्थिक व्यवस्था बीमार होती जा रही है, सामाजिक और राजकीय व्यवस्था भी पतित होती जा रही है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, जाति-आधारित समाज व्यवस्था जिसके चलते दलितों पर रोज अत्याचार हो रहे हैं, एक सांप्रदायिक राजनीतिक व्यवस्था जो लोगों को धर्म के नाम पर बांटकर उनमें एक-दूसरे के प्रति नफरत भर रही है, एक सड़ी-गली मूल्य व्यवस्था जो तुच्छ स्वार्थों को और असंवेदनशीलता व उदासीनता को बढ़ावा दे रही है — यह आज की सच्चाई है।

आम लोग भारतीय संविधान के प्रति इस विश्वासघात को मूकदर्शी बने नहीं देख रहे हैं। जैसे वसंत ऋतु आने पर हर तरफ फूल खिलने लगते हैं, देश भर में जगह-जगह पर लोग एकत्रित हो रहे हैं, छोटे-छोटे संघटन बना रहे हैं और संघर्ष की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हालांकि ये संघर्ष अभी छोटे हैं, बिखरे हुए हैं, देश का भविष्य इन्हीं शानदार संघर्षों में है। जैसे-जैसे और लोग इन संघर्षों में शामिल होंगे, ये शक्तिशाली होंगे, इकट्ठे होंगे और समाज परिवर्तन के लिये प्रबल ताकत बन जायेंगे।

हमें निराशा और तटस्थता छोड़नी चाहिये, एक सुंदर भविष्य का सपना देखना चाहिये, विश्वास करना चाहिये कि दुनिया बदली जा सकती है। हां, 'दूसरा जग संभव है'। लेकिन इसको यथार्थ में लाने के लिये हमें अपने छोटे-छोटे प्रयास शुरू करने होंगे। जिस तरह हिमालय से उतरने वाले झरने मिलकर विशाल गंगा बनाते हैं, उसी तरह हमारे ये संघर्ष भी भविष्य में एक साथ आयेंगे और एक शक्तिशाली और राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा होगा जो साम्राज्यवादी वैश्वीकरण को चुनौती देगा और हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्त्वों में निहित सपनों के अनुरूप एक नये समाज की स्थापना करेगा। इसलिये हमने इस मंच की, **लोकायत** की, स्थापना की है।

हम पुणे मे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं:

- बढ़ती महंगाई, अत्यावश्यक सेवाओं का निजिकरण और व्यापारीकरण, शहरों की दयनीय सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, आण्विक ऊर्जा की घातकता, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के दुष्प्रभाव, विकास के नाम पर लाखों लोगों की जीविका को नष्ट कर लागू किये जा रहे कॉरपोरेट घरानों के प्रकल्प, जैसे प्रश्नों पर जनजागृति करते हैं और लोगों को संघटित करने का प्रयास करते हैं। इन जनजागृति अभियानों में हम पोस्टर प्रदर्शनी, फिल्म महोत्सव, नुक्कड़ नाटक, गीत जैसे विविध कलात्मक माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं व सेमिनार-व्याख्यान-धरने-रैलियों का आयोजन करते हैं।
- हमने सांप्रदायिक दंगे, जातीय शोषण, अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा तीसरी दुनिया के देशों पर फौजी आक्रमण, वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर सेमिनार और विरोध प्रदर्शन आयोजित किये हैं।
- 'अभिव्यक्ति' लोकायत की महिला इकाई है जो कि महिलाओं के विविध प्रश्नों पर सामाजिक बोध का निर्माण करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है।
- लोकायत का एक सक्रिय सांस्कृतिक मंच भी है जो विभिन्न कला-माध्यमों का प्रयोग कर लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना उन्नत करने का प्रयास करता है।
- इन सभी प्रश्नों पर काम करते हुए जरूरी विषयों पर हम पुस्तिकायें और पर्चे भी प्रकाशित करते हैं।

दोस्तों, यदि आप हमारे बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं, तो आप हमसे निम्न पतों पर संपर्क कर सकते हैं:

संपर्क पता

लोकायत, सिंडिकेट बैंक के सामने, लॉ कॉलेज रोड, नल स्टॉप के पास, पुणे - 411004

(हर रविवार को शाम 5 से 7 बजे बैठक होती है)

संपर्क फोन	ऋषिकेश येवलेकर	94235 07864	अलका जोशी	94223 19129
Website	http://lokayat.org.in		**Email**	lokayat.india@gmail.com
Mailing List	pune.lokayat@lists.riseup.net		**Facebook**	www.facebook.com/lokayat.india

इस पत्रक को अलका जोशी ने लोकायत के लिये १/१२/१४ को पुणे मे प्रकाशित किया